सं.ए-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांकः 31 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित नवम्बर, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सु.पा.सिंह 31.12.2019

(सुरिन्दर पाल सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23092100

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
   सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी।
10. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
11. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
12. डा. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
13. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (प्रशासन एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग
14. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
15. सुश्री मीरा स्वरूप, अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (सीएंडसी/यूएनएंडओएमआई)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (एफएम)/संयुक्त सचिव (बीसी एंड आईईआर)/सलाहकार (आईईआर)/सीएएए।
18. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
19. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
20. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
21. गार्ड फाइल - 2019

सं. ए-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषय: नवम्बर, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को जारी सकल घरेलू उत्पाद आकलनों के अनुसार जीडीपी बढ़त गत वर्ष की समान तिमाही में दर्ज की गई 7.0 प्रतिशत बढ़त की तुलना में दूसरी तिमाही (जुलाई से सितम्बर) में जीडीपी बढ़त 4.5 प्रतिशत थी।

1.2 कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों हेतु क्रमशः 2.1 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की क्षेत्रीय बढ़त के साथ वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 4.3 प्रतिशत तक बढ़ा।

1.3 वर्ष 2018-19 हेतु राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमानों के अनुसार जीडीपी बढ़त 2018-19 में 6.8 प्रतिशत थी। 2016-17 और 2017-18 में जीडीपी बढ़त क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत तक उच्चतर थी।

1.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला-संयुक्त) पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति अक्तूबर, 2018 में 3.38 प्रतिशत की तुलना में अक्तूबर, 2019 में 4.62 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मूद्रास्फीति अक्तूबर, 2018 में 5.54 प्रतिशत की तुलना में अक्तूबर, 2019 में 0.16 प्रतिशत रही। औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दृष्टि से मुद्रास्फीति सितम्बर, 2018 में 5.61 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर 2019 में 6.98 प्रतिशत थी। अक्तूबर, 2019 में कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमश: 8.11 प्रतिशत और 7.93 प्रतिशत रही।

1.5 अक्तूबर 2019 में पॉलिसी रेपो दर 5.40 प्रतिशत से 25 बीपीएस कम हो कर 5.15 प्रतिशत हो गई। यह 2019 में मौद्रिक नीति समिति द्वारा की गई पांचवीं कटौती थी। पिछले वर्ष की समान अवधि में 14.6 प्रतिशत की तुलना में अक्तूबर, 2019 के अंत में बैंक साख बढ़त 8.9 प्रतिशत हो गई। 09 नवम्बर, 2018 को 7.81 प्रतिशत की तुलना में 8 नवम्बर, 2019 को 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 6.67 प्रतिशत रहा।

1.6 भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 15.8 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.3 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 14.3 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.0 प्रतिशत) हो गया। लेकिन बाद की तिमाही में 4.6 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) से उच्च था। प्राथमिक रूप से एक वर्ष पूर्व 29.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 31.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की उच्च अदृश्य

प्राप्तियों को देखते हुए चालू खाता घाटा की संविदा वर्ष दर वर्ष आधार पर होती है। विशेष रूप से पर्यटन, वित्तीय सेवाओं और दूर संचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में बढ़त को देखते हुए निवल सेवा प्राप्तियां वर्ष दर वर्ष आधार पर 7.3 प्रतिशत तक बढ़ी। निजी लेनदेन प्राप्तियां, मुख्यतः वे प्राप्तियां जो विदेश में नियुक्त भारतीयों द्वारा विप्रेषित धन का प्रतिनिधित्व करती है, 19.9 बिलियन अमरीकी डॉलर पहुंच गई जिसमें वर्ष पूर्व अपने स्तर से 6.2 प्रतिशत की वृद्धि रही। वित्तीय खाते में निवल विदेशी सापेक्ष निवेश 2018-19 की पहली तिमाही में 9.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 13.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था। ऋण और इक्विटी बाजारों दोनों में कुल खरीद के चलते 2018-19 की पहली तिमाही में 8.1 बिलियन अमरीकी डालर के बर्हिवाह की तुलना में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 4.8 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया। वर्ष पूर्व 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के बर्हिवाह की तुलना में वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधारों के चलते निवल अंतर्वाह 6.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा। वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 11.3 बिलियन अमरीकी डालर की कमी की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडारों (बीओपी आधार पर) में 14.0 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त रही।

1.7 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च अंत, 2019 के 411.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 30.7 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त दर्शाते हुए 25 अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 442.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। सितम्बर, 2019 में 71.33 रुपए प्रति अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की औसत मासिक विनिमय दर (संदर्भ दर) अक्तूबर, 2019 माह में 71.04 रुपए प्रति अमरीकी डालर रही।

1.8 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में सितम्बर, 2018 में 4.6 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में सितम्बर, 2019 में (-) 4.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। संचयी आधार पर अप्रैल से सितम्बर, 2019-20 की अवधि हेतु औद्योगिक बढ़त अप्रैल से सितम्बर, 2018-19 के दौरान 5.2 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में 1.3 प्रतिशत थी। आठ मुख्य उद्योगों में अक्तूबर, 2018 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में अक्तूबर, 2019 में 5.8 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।

1.9 भारत का व्यापारिक माल निर्यात अक्तूबर, 2018 के दौरान 26.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हुए अगस्त, 2019 के दौरान 26.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत का आयात अक्तूबर, 2018 में 44.7 बिलियन अमरीकी डालर के आयात मूल्य के स्तर की तुलना में 13.4 प्रतिशत घटकर अक्तूबर 2019 के दौरान 37.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत का तेल आयात अक्तूबर, 2019 के दौरान अक्तूबर 2018 की तुलना में क्रमशः 31.7 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत तक घट गया।

1.10 व्यापार घाटा अक्तूबर, 2018 के दौरान 18.0 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में अक्तूबर, 2019 में 11.0 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

1.11 सितम्बर, 2019 के दौरान सेवाओं का निर्यात और आयात क्रमश: 17.5 बिलियन अमरीकी डालर और 11.1 बिलियन अमरीकी डालर रहा। सितम्बर, 2019 के लिए सेवाओं में व्यापार संतुलन 6.4 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित है।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 (क) 20 नवम्बर, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन किए जाने के बाद 25 नवम्बर, 2019 को लोक सभा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण विधेयक - 2019 लाया गया।

(ख) टास्क फोर्स ऑन नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की पहली बैठक दिनांक 09.09.2019 को आयोजित की गई थी और अब तक इस टास्क फोर्स की 19 बैठकें हो चुकी हैं। नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। भारत में पहली बार इस तरह का कोई कार्य किया जा रहा है। इससे अवसंरचनागत परियोजना तैयारी में सुधार आने, समय और लागतों में कमी आने और अवंसरचना में विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

(ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) ने अपनी 90वीं बैठक में केप आकार के जहाजों को पीपीपी मोड में लेने हेतु वैस्टर्न डाक कैप्टिव बर्थ के निर्माण सहित पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) इनर हार्वर सुविधाओं को गहरा करने और इष्टतम करने हेतु पोत मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

(घ) भारत सरकार द्वारा 01 मार्च, 2012 को "फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरैन्जमेंट फॉर सार्क कंट्रीज" का अनुमोदन किया गया। यह रूपरेखा विदेशी विनिमय आवश्यकताओं हेतु वित्तपोषण की सुविधा मुहैया कराने अथवा दीर्घावधि व्यवस्थाएं पूर्ण होने तक भुगतान संतुलन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस सुविधा के तहत आरबीआई प्रत्येक सार्क सदस्य देश (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) को न्यूनतम 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिकतम 400 मिलियन अमरीकी डॉलर विस्तार के अध्यधीन उनके दो महीनों की निर्यात आवश्यकता और अमरीकी डॉलर या यूरो या भारतीय मुद्रा में कुल 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा तक विभिन्न आकारों के स्वैप की सुविधा देता है। देश विशिष्ट सीमाओं के अतिरिक्त एक अनुमोदित रूपरेखा के भीतर 400 मिलियन अमरीकी डॉलर के "स्टैन्ड बाई स्वैप" का भी प्रावधान है जोकि 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की सुविधा के संपूर्ण आकार के भीतर उपलब्ध उपयोग न हुई शेष राशि से चलाई जाती है। "स्टैण्ड बाई स्वैप" सुविधा जनवरी, 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से उन सार्क सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त स्वैप अनुरोध को पूरा करने हेतु किया गया था जो अपनी देश विशिष्ट सीमा को पार कर जाते हैं। इससे पूर्व 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और वर्ष 2017 में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा रूपरेखा की समय सीमा बढ़ाई गई थी। रूपरेखा की समय सीमा 13 नवम्बर, 2019 के बाद समाप्त होनी तय की गई थी। माननीय वित्त मंत्री द्वारा कुछ संशोधनों के बाद 'सार्क देशों हेतु मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर रूपरेखा' पुनः 13 नवम्बर, 2022 तक तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। अब तक भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने इस सुविधा का उपयोग किया है।

(ङ) संकट ग्रस्त आवासन परियोजनाओं हेतु मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 06.12.2019 को 25000 करोड़ रुपए की वैकल्पिक विकास निधि के रूप में "वहनीय और मध्यम आय आवासन हेतु विशेष खिड़की (एसडब्ल्यूएएमआईएच)" की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। पहला फंड एसडब्ल्यूएएमआईएच एआईएफ-I पंजीकृत किया गया और तत्पश्चात् निवेश समिति गठित की गई।

2.2 वित्त मंत्री के अनुमोदन से नवम्बर, 2019 के दौरान आठ ऋण श्रंखलाओं (एलओसी) का विस्तार किया गया, जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	देश का नाम	मिलियन/(अमरीकी डालर)	परियोजना	अनुमोदन की तारीख
1.	माली सरकार	60.65	फाना, माली में 50 मेगावाट के सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र के लिए	07.11.2019
2.	गिनी सरकार	20.22	दो सौर परियोजनाओं के लिए	07.11.2019
3.	सूरीनाम सरकार	35.80	सूरीनाम के 50 दूरस्थ गांव में सौर डीजी हाइब्रिड पीवी प्रणालियों के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना शुरू करने के लिए	14.11.2019
4.	रवांडा सरकार	122.00	दो सौर परियोजनाओं के लिए	14.11.2019
5.	बोलीविया सरकार	100.00	बोलीविया में विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए	14.11.2019
6.	श्रीलंका सरकार	400.00	विकास और अवसंरचना परियोजनाएं शुरू करने के लिए	13.11.2019
7.	गिनी सरकार	170.00	ग्रैंड कोनाक्री-होराइजन 2040 की पेय जल आपूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु।	13.11.2019
8.	सेशेल्स	100.00	रक्षा संबंधी उपकरणों और वाहनों की खरीद, उन्नयन, रखरखाव और रक्षा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु	29.11.2019

2.3 अक्तूबर, 2019 तक के व्यय की 2019-20 के लिए बजटीय अनुमान से तुलना

अक्तूबर, 2019 माह के मासिक खातों के अस्थायी अलेखापरीक्षित विवरण अनुरूप अक्तूबर, 2019 तक कुल गैर-ऋण प्राप्तियां 9,34,460 करोड़ रुपए थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 2018-19 के 44.4% बजट अनुमान की तुलना में 44.9% है। वर्ष 2019-20 में सीओपीपीवाई में 45.7% की तुलना में कुल राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान का 46.2% थीं। अक्तूबर, 2019 के अंत तक सकल कर राजस्व बजट अनुमान का 42.7% था (सीओपीपीवाई - बजट अनुमान का 45.7%)। कर राजस्व (निबल) बजट अनुमान का 41.4% था (सीओपीपीवाई में 44.7%) जबकि गैर-कर राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान का 71.6% थी (सीओपीपीवाई में 52.1%)। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां बजट अनुमान का 22.4% थी (सीओपीपीवाई में 20.8%) खर्च की दृष्टि से अक्तूबर, 2019 के अंत तक कुल व्यय 16,54,905 करोड़ रुपए था जो बजट अनुमान का 59.4% है (सीओपीपीवाई में 59.6%)। इसमें बजट अनुमान (सीओपीपीवाई में 59.7%) के

59.4% का राजस्व व्यय और बजट अनुमान के 59.5% का पूंजी व्यय (सीओपीपीवाई में 59%) शामिल है। ब्याज भुगतान सीओपीपीवाई में 50.7% की तुलना में बजट अनुमान का 43.8% था।

2.4 नवम्बर, 2019 माह के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:-

i. माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने नई दिल्ली में दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को हुई मंत्रिमंडल स्तर की भारत- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और वित्तीय भागीदारी वार्ता की सातवीं बैठक में सम्मिलित होकर भारतीय शिष्टमंडल की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री और अमरीकी वित्त मंत्री के बीच एक सांझा बयान पर हस्ताक्षर हुए।

ii. माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में सचिव (आर्थिक कार्य) ने दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की 21वीं बैठक में भाग लिया।

iii. सचिव (आर्थिक कार्य) ने दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को हुई वैश्विक विकास नैटवर्क (जीडीएन) की बैठक में भाग लिया।

iv. सचिव (आर्थिक कार्य) ने बेसल III विनियम और बैंकिंग क्षेत्र और एमएसएमई पर उनके प्रभाव के संबंध में नई दिल्ली में 13 नवम्बर, 2019 को हुई बैठक में भाग लिया।

v. सचिव (आर्थिक कार्य) ने उच्च गुणवत्ता वाले डाटा की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सांख्यिकीय प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर विचार करने हेतु 14 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भाग लिया।

vi. श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबी और एडीबी) ने आर्थिक कार्य विभाग की संचालन समिति की 101वीं बैठक की अध्यक्षता की जो कि 19 नवम्बर, 2019 को हुई।

vii. बजट उद्घोषणाओं के प्रभाव मूल्यांकन और मुख्य नीतिगत सुधार क्षेत्रों पर यथा समय विश्लेषण हेतु विश्व बैंक से तकनीकी सहायता पर विचार विमर्श करने हेतु श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबी और एडीबी) की अध्यक्षता में दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को एक बैठक हुई।

viii. श्री समीर खरे, अपर सचिव (एफबी और एडीबी) ने विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजनाओं के क्रमवार समीक्षा के संबंध में 18 नवम्बर, 2019 को हुई बैठक की भी अध्यक्षता की।

ix. डॉ. सी.एस. मोहापात्रा, अपर सचिव (बीसी) ने अपर सचिव, न्यूजीलैण्ड कोष के साथ 28.11.2019 को नई दिल्ली में हुई 7वीं इण्डिया-न्यूजीलैण्ड आर्थिक नीति वार्ता बैठक की सह-अध्यक्षता की।

x. इंडो-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के तहत नई दिल्ली में 27 नवम्बर, 2019 को इंडो-जर्मन वार्षिक समझौता बैठक 2019 हुई। भारत की ओर से अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग

डॉ सी.एस. महापात्रा और जर्मनी की ओर से महानिदेशक, संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय डॉ. क्लॉडिया वार्निंग ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की थी।

3. **न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन**

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. **एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना**

शून्य।

5. **माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति**

विभाग में अनुमोदन हेतु लंबितः 05

****